फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 90 प्रभात जयपुर, शनिवार, 1 नवम्बर, 2025 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

THE SOUL OF THE ROSE

Waterhouse's title is loosely derived from Chaucer's dream poem, *The Romaunt of the Rose*, adapted from the 13th Century French romance: *Roman de la Rose* by Guillaume de Lorris

Don't Burn It, Use It!

The Logical Loose Sometimes | The Fatal Logic of the Physicist: A Cautionary Tale of Last Words

कांग्रेस की अव्यवस्था कहीं भारी न पड़ जाए, महागठबंधन की उम्मीदों पर

पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया था

- रेणु मित्तल -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली 31 अक्टूबर। बिहार में कांग्रेस पूरी तरह से दिशाहीन और बिखरी हुई नज़र आ रही है। पार्टी चुनाव प्रचार की कोई ठोस रणनीति नहीं बना पा रही। और बुरी तरह लड़खड़ा रही है। यह आशंका जताई जा रही है कि कांग्रेस की नाकामी एक बार फिर महागठबंधन की सीटों को कम कर देगी, जैसा पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ था, जब कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के कारण तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा था।

- राहुल गांधी के खासमखास, महारथी कृष्णा अल्लूवेरा तो अपनी अकड़ में गठबंधन ही तोड़ देने वाले थे।
- इसके बाद हालात संभालने के लिए एक और महारथी, अशोक गहलोत को भेजा गया, जो हालात ठीक करने की बजाय तेजस्वी के सामने पूरी तरह से झुक गए।
- अब आए हैं, अविनाश पांडे, जिनकी स्थिति एक असफल प्रभारी की है। राजस्थान में कांग्रेस की बजाय वे गहलोत के लिए काम करते रहे, यही नहीं, तत्कालीन हैल्थ मिनिस्टर के साथ व्यावसायिक हित भी साधा था।
- सार यह है, कि बिहार में कांग्रेस संगठन इस कदर बदहाल हैं कि महागठबंधन के घटक दलों, खासकर आरजेडी में डर है कि कहीं कांग्रेस के कारण फिर से लुटिया न डूब जाए।

राहुल गांधी के नवरत्नों में से एक कृष्णा अल्लुवेरा बिहार में एकदम असफल रहे हैं और उनकी अकड़ ने राजद के साथ गठबंधन को टूटने के कगार पर पहुँचा दिया। इसके बाद के.सी. वेणुगोपाल ने हालात संभालने के लिए अशोक गहलोत को भेजा, लेकिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत तेजस्वी के सामने झुक गए और गठबंधन में संतुलन नहीं बना सके।

अब वेणुगोपाल ने अविनाश पांडे को बिहार भेजा है, ताकि वे चुनाव अभियान को संभालें, तेजस्वी पर नज़र रखें और गठबंधन में तालमेल बनाए रखें। अविनाश पांडे नियंत्रण कक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे और राहुल गांधी व तेजस्वी यादव की संयुक्त रैलियों का समन्वय करेंगे। वे तेजस्वी से सीधा संपर्क बनाए रखेंगे, क्योंकि अल्लुवेरा अब पूरी तरह हाशिए पर जा चुके हैं।

चुनाव प्रबन्धन में राहुल गांधी की युवा टीम के असफल रहने के बाद वेणुगोपाल वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतार रहे हैं, ताकि स्थिति संभाली जा सके। लेकिन अविनाश पांडे का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। राजस्थान में प्रभारी रहते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत के समर्थक के रूप में काम किया, न कि एक निष्पक्ष एआईसीसी महासचिव की तरह। उन पर आरोप है कि उन्होंने उस समय के स्वास्थ्य मंत्री के साथ व्यावसायिक संबंध रखे और दोनों ने मिलकर काफी लाभ कमाया।

इसके बाद उन्हें झारखंड भेजा गया, जहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अब हाई कोर्ट को बम से उड़ाने का ई-मेल आया

जयपुर, 31 अक्टूबर। सैशन कोर्ट में बम ब्लास्ट की दो बार धमकी देने के बाद, इस बार राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उडाने की धमकी दी गई है। हाईकोर्ट प्रशासन के आधिकारिक मेल आईडी पर यह मेल भेजा गया। हालांकि हर बार की तरह पुलिस को तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और यह सिर्फ धमकी निकली।

जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट में जजों की ओर से मुकदमों की सुनवाई आरंभ करने के दौरान हाईकोर्ट प्रशासन को मेल की जानकारी मिली। प्रशासन ने

- पुलिस ने पूरा परिसर खाली कराकर सघन चैकिंग की। कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

तुरंत इसकी सूचना कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य सभी जजों और कर्मचारियों को दी और पुलिस प्रशासन को भी सूचना भेजी गई। जजों ने तुरंत मुकदमों की सुनवाई बंद कर दी और कोर्ट रूम छोड़ दिया। दूसरी ओर पुलिस की विभिन्न एजेंसियों के आलाधिकारी, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचे। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने हाईकोर्ट के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली, लेकिन कहीं कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। वहीं पुलिस आईपी एड्रेस के जरिए भी ई-भेज भेजने वाले का पता लगा रही है। मेल में कहा गया है कि तमिलनाडु में कुछ पत्रकारों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीतीश कुमार की 26 सैकैंड की उपस्थिति ज्यादा चर्चित रही

हालांकि घोषणा पत्र में कई मनलुभावन वादे किए गए थे

- श्रीनंद झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर। जिस दिन एनडीए ने अपना साझा घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें एक करोड़ नौकरियों, एक करोड़ लखपति दीदियों और कृषि के लिए एक लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गई, उस दिन सुर्खियों में रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घोषणा पत्र जारी करने के कार्यक्रम में बेहद कम समय के लिए उपस्थित रहना और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिए बिना वहाँ से चले जाना।

एनडीए खेमे में सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि चुनाव में जीत की स्थिति में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने को लेकर भाजपा का रुख आखिर क्या होगा।

घोषणा पत्र जारी करने के कार्यक्रम में नीतीश कुमार की बेहद अल्प मौजूदगी ने इस अटकल को और मजबूत कर दिया कि वे एनडीए के संयुक्त कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं। इससे विपक्ष को भी यह कहने का मौका मिला कि भाजपा और जदयू के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। कांग्रेस ने नीतीश कुमार की 26 सेकंड की मौजूदगी को यह कहकर तूल दिया कि मुख्यमंत्री ने अपमानित महसूस किया। बिहार पर्यवेक्षक फैजान अहमद के अनुसार, भाजपा नेता कहते

- घोषणा पत्र की बारीकियाँ समझाने की जिम्मेवारी उपमुख्यमंत्री व भाजपा नेता सम्राट चौधरी को पूरी करनी पड़ी।
- घोषणा पत्र में एनडीए ने सात एक्सप्रेसवे, छत्तीस सौ किलोमीटर रेल लाईन व पटना, दरभंगा, पूर्णिया को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए उपयुक्त बनाने का वादा किया है।
- इसी प्रकार दस नये इण्डस्ट्रियल पार्क हर जिले में, सौ एमएसएमई हब्स व पचास हजार कुटीर उद्योग लगाने की बात की गई है।
- घोषणा पत्र में एक लाख करोड़ रूपए की लागत से कृषि क्षेत्र में तथा हर फसल के लिए न्यूनतम एमएसपी की बात भी कही गई है।

तो हैं कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि जीत के बाद वे अगले पाँच साल मुख्यमंत्री बने रहेंगे।

नीतीश की अनुपस्थिति में उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने घोषणा पत्र की विस्तार से व्याख्या की। घोषणा पत्र (69 पेज) के अनुसार, बिहार में सात एक्सप्रेस-वे और 3600 किलोमीटर रेल मार्ग बनाए जाएंगे, जबकि पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर के हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिया जाएगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अज़हरुद्दीन ने तेलंगाना में मंत्री पद की शपथ ली

भाजपा ने इस नियुक्ति का भारी विरोध किया तथा चुनावी लाभ के लिए उठाया गया कदम बताया

-जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर। भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन को शुक्रवार को तेलंगाना कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। राज्यपाल जिश्नु देव वर्मा ने शुक्रवार सुबह राजभवन में पूर्व क्रिकेटर को शपथ दिलाई।

- ज्ञातव्य है कि तेलगांना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर 11 नवम्बर को उपचुनाव है और यहाँ 30 प्रतिशत मतदाता मुसलमान हैं।
- असल में अज़हरुद्दीन न तो विधानसभा के सदस्य हैं, न ही विधान परिषद के, ऐसे में उन्हें मंत्री बनाया जाना सवाल तो खड़े करता ही है।

उनकी नियुक्ति से न केवल लंबे समय से रिक्त पड़ा पद भर गया है, बल्कि कांग्रेस को कैबिनेट में पहली बार मुस्लिम प्रतिनिधित्व भी मिल गया है।

तेलंगाना में विपक्ष ने इसे एक चुनावी दांव बताया, जिसका उद्देश्य 11 नवंबर को होने वाले जुबली हिल्स उपचुनाव में मुस्लिम वोटरों को आकर्षित करना है, जहाँ अनुमानित रूप से 30 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं।

नियुक्ति के समय पर आपत्ति जताते हुए, भाजपा ने मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) को पत्र लिखा और कांग्रेस पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा कि इस समय मंत्री पद दिया जाना, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति को, जो हाल ही में उसी सीट से टिकट मांग चुका हो, आधिकारिक शक्ति का दुरुपयोग तथा जो मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास है।

सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इसे सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता को पूरा करने के रूप में सही ठहराया। तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख महेश गौड़ ने कहा, "कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यकों को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का वादा किया था। पूर्व आंध्र प्रदेश सरकारों में भी हमेशा एक अल्पसंख्यक चेहरा शामिल किया जाता रहा है। हम सिर्फ एक लंबित असंतुलन को सुधार रहे हैं।"

अजहरुद्दीन अभी तक न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के सदस्य, जो राज्य मंत्री बनने के लिए आवश्यक है। वे राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद के लिए नामित किया जा चुके हैं, लेकिन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'आरोपी के वकील को समन नहीं भेज सकती जांच एजेंसी'

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी जांच एजेंसी किसी वकील को उसके मुवक्किलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए समन जारी नहीं कर सकती, जब तक कि वह प्रासंगिक कानून के तहत स्पष्ट रूप से अनुमत न हो। सर्वोच्च न्यायालय

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस बड़े फैसले में कहा कि मुवक्किल की जानकारी पाने के लिए उसके वकील से पूछताछ नहीं की जा सकती।

ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दो वरिष्ठ वकीलों को जारी समन को रद्द कर दिया और जांच एजेंसियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए, जिनके तहत वकीलों को उनके मुवक्किलों को दी गई कानूनी सलाह के संबंध में पूछताछ के लिए तलब करने पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई निर्देश जारी किए ताकि जांच एजेंसियां अभियुक्तों को दी गई कानूनी सलाह के संबंध में वकीलों को मनमाने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इंगलैंड के महाराजा चार्ल्स के भाई एन्ड्रयू का टाइटल उससे छीना गया

अब वे अपने टाइटल में निहित अन्य सुविधाएं नहीं भोग पाएंगे। जैसे विंडसर कासल में स्थित अपना मैन्शन उन्हें खाली करना पड़ेगा

- अंजन रॉय -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर। ब्रिटिश शाही परिवार हाल ही में एक बेहद शर्मनाक और दुखद प्रकरण से गुजरा है, जिसका अंत एक ऐसे शाही सदस्य के निष्कासन के रूप में हुआ, जो ब्रिटिश सिंहासन की उत्तराधिकार सूची में आठवें स्थान पर है।

किंग चार्ल्स ने अपने छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू से उनकी शाही उपाधि छीनने की घोषणा की है। अब वे केवल मिस्टर एंड्रयू माउंटबैटन विंडसर कहलाएँगे। साथ ही, उन्हें विंडसर कैसल के परिसर में स्थित उस शाही भवन से भी निकाल दिया जाएगा, जहाँ वे पिछले बीस वर्षों से रह रहे थे।

यह कहानी ऊँचे पदों पर बैठे लोगों द्वारा विशेषाधिकारों के दुरुपयोग और अनुचित आचरण की है। एंड्रयू के इर्द-गिर्द विवाद लंबे समय से चल रहे थे और इसी कारण उन्हें शाही परिवार के

- उनको अब ब्रिटिश सरकारी खज़ाने से न तो वेतन, न भत्ता मिलने का अधिकार होगा।
- एन्ड्रयू पर सैक्स दलाल जैफरी एप्स्टीन द्वारा उपलब्ध कराई गई बच्चियों के साथ सैक्स का आरोप है।
- रॉयल फैमिली के सदस्य एडवर्ड द सिक्स्थ को एक साधारण तलाकशुदा महिला से विवाह के आरोप में टाइटल से मुक्त किया गया था, उसी समय दो तीन अन्य रॉयल फैमिली के सदस्यों से टाइटल वापस लिया गया था, क्योंकि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन सेना के साथ भाग लिया था।

वरिष्ठ सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने के लिए कहा गया था।

शाही कार्यालय ने केवल इतना कहा है कि एंड्रयू ने "अपने निर्णय में गंभीर भूलें की हैं।" यह टिप्पणी उनके उस विवादित संबंध की ओर इशारा करती है, जो उन्होंने जेफ्री एप्स्टीन से रखा था, वह व्यक्ति, जिस पर किशोरियों के साथ यौन उत्पीड़न और उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए मानव तस्करी जैसे अपराधों के आरोप लगे थे।

ब्रिटिश इतिहासकारों का कहना है कि शाही परिवार में इतनी गंभीर स्थिति पिछली बार 1936 में आई थी, जब राजा एडवर्ड अष्टम ने एक विवाहित सामान्य महिला से विवाह करने के लिए अपना सिंहासन त्याग दिया था। इससे पहले 1917 में भी कुछ शाही सदस्यों को उनकी "प्रिंस" की उपाधि से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि वे जर्मन सेना के साथ युद्ध में शामिल हुए थे।

तथापि, कई लोगों का कहना है कि वर्षों से जिन गतिविधियों में एंड्रयू लिप्त रहे हैं, उसके लिए सिर्फ उनकी उपाधि छीन लेना पर्याप्त नही है। हालांकि एंड्रयू इन आरोपों का खंडन करते रहे हैं। उनके पतन की असली वजह वर्जीनिया जूफ्रे की आत्मकथात्मक पुस्तक का प्रकाशन माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि किशोरावस्था में एंड्रयू ने उनका यौन शोषण किया था।

आम कानून के तहत यदि कोई साधारण नागरिक ऐसे अपराधों में दोषी पाया जाता, तो उसे सख्त सजा और जेल दोनों होतीं। लेकिन एंड्रयू को फिलहाल केवल उनकी शाही पहचान से वंचित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोनिया, खड़गे व राहुल ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी

नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी तथा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 41वें शहादत दिवस पर शुक्रवार को उन्हें नमन करते हुए

- तीनों नेताओं ने स्व. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समाधि स्थल "शक्ति स्थल" पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भी शिरकत की।

श्रद्धांजलि अर्पित की।

खड़गे, सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी ने सुबह पूर्व प्रधानमंत्री कि समाधि शक्ति स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंच कर पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सस्ती थोथी नारेबाजी का लगातार इस्तेमाल करके ट्रंप अधिनायकवाद की सीमा पार कर गए

यह यात्रा केवल ट्रंप ही नहीं, तुर्की के एर्दोआन, हंगरी के विक्टर ओरबान और फिलीपीन्स के रोड्रिगो दुतेर्ते इस यात्रा को पहले ही पूरी कर चुके हैं

- सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर। डॉनल्ड ट्रंप का वर्तमान रुख आधुनिक तानाशाही के शुरुआती दौर जैसा लगता है और इसकी तुर्की के रेशप ताइप एर्दोआन, फिलीपींस के रोड्रिगो दुतेर्ते और हंगरी के विक्टर ऑर्बन जैसे नेताओं से कई समानताएँ हैं।

सबसे स्पष्ट समानता घरेलू नीति के सैन्यीकरण में देखी जा सकती है। रोड्रिगो दुतेर्ते ने "नशीली दवाओं पर युद्ध" में कानून व्यवस्था और युद्ध के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया, जिससे जन सुरक्षा के नाम पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत हत्याएं आम हो गईं। अमेरिकी शहरों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अमेरिकी सेना तैनात करने की ट्रंप की इच्छा भी इसी रणनीति का अनुसरण करती है। "शहरों को सुरक्षित बनाया जा सके।" इसी प्रकार के रास्ते पर चलती है। दोनों मामलों में राज्य अपनी सशस्त्र शक्ति को जनता के खिलाफ मोड़ देता है, नागरिक समस्याओं को सैन्य खतरे के रूप में परिभाषित करता है। लक्ष्य, "मादक पदार्थों के तस्कर", "अवैध अप्रवासी", या "भीतरी दुश्मन", पर इन्हें इतना अस्पष्ट रखा जाता है कि व्यापक बल प्रयोग को बिना जिम्मेदारी के साथ न्यायसंगत ठहराया जा सके।

ट्रंप भी एर्दोआन के लोकतांत्रिक संस्थानों को कमज़ोर करने के पैटर्न का पालन करते हैं। एर्दोआन ने धीरे-धीरे तुर्की की न्यायपालिका, सैन्य स्वतंत्रता और प्रेस को कमज़ोर किया, साथ ही वह राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने का दावा भी करते रहे। ट्रंप द्वारा अपने निर्देशों का पालन नहीं करने वाली उन अदालतों, अभियोजकों और राज्यपालों पर हमला करना इसी प्रवृत्ति को दर्शाता है कि वे कार्यकारी शक्ति पर किसी भी नियंत्रण को नकारने के लिए विरोध को

- इन अधिनायकों ने यह जान लिया है कि सत्ता लगातार भय पैदा करके ही पाई जाती है।
- ट्रंप भी प्रजातंत्र के प्रतीकों का इस्तेमाल करके शासन करना चाहते हैं। पर, प्रजातंत्र की भावना व चिंतन का नितांत अभाव है।

विश्वासघात के रूप में पेश किया जाए। एर्दोआन की तरह ट्रंप भी आलोचकों को देशद्रोही व डीपस्टेट साजिश का अंग बताते हैं और असंतोष को धोखा बताते हैं।

चुनावी वैधता पर उनके हमले की तुलना विक्टर ऑर्बन द्वारा हंगरी की लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ हेराफेरी करने से की जा सकती है। ऑर्बन ने चुनावी कानूनों को फिर से परिभाषित किया और मीडिया पर कड़ा नियंत्रण रखा, ताकि स्थायी लाभ सुनिश्चित किया जा सके और लोकतंत्र का दिखावा किया, पर उसकी वास्तविकता को खत्म कर दिया। ट्रंप का 2020 के चुनाव परिणामों को स्वीकार करने से इनकार और उनका बार-बार वोट चुराने का दावा करना यह दिखाता है, उनके दृष्टिकोण में, लोकतंत्र केवल तब तक वैध है जब वह जीतते हैं।

फिर बारी आती है, स्वतंत्र प्रेस पर हमला करने की। जो हर तानाशाह की पहचान है। एर्दोआन, दुतेर्ते और ऑर्बन ने स्वतंत्र पत्रकारों को भ्रष्ट या शत्रुतापूर्ण शक्तियों द्वारा नियंत्रित बताया। ट्रंप का "फेक न्यूज़ मीडिया" के खिलाफ लंबा अभियान, जिसकी परिणती सैनिकों से पत्रकारों का मज़ाक उड़ाने की अपील करने पर हुई, उसी परंपरा का हिस्सा है। जब नागरिक स्वतंत्र रिपोर्टिंग पर अविश्वास करने लगते हैं तो तथ्य की जगह दुष्प्रचार ले लेता है और नेता ही सत्य का एकमात्र निर्णायक बन जाता है।

एक और प्रमुख विशेषता है, व्यक्तित्व का पंथ (कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी) है, अर्थात नेता अपनी छवि को इतना बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है कि लोग उसे महानायक मानते हैं। इतिहास में पुतिन से लेकर मुसोलिनी तक, तानाशाहों ने अपनी छवि के मिथक के आधार पर अपनी ताकत बढ़ाई। मानो वे अकेला उद्धारक हैं, जो राष्ट्र की किस्मत का प्रतीक है। ट्रंप भी खुद को ऐसे बताते हैं मानो सिर्फ वे ही "असली अमेरिकियों" की रक्षा करने, ईसाई धर्म को बचाने और व्यवस्था बहाल करने में एकमात्र सक्षम व्यक्ति हैं। उनका आंदोलन विचारों या संस्थाओं के बजाय, केवल उनके प्रति व्यक्तिगत निष्ठा के चारों ओर घूमता है।

तानाशाह "भीतरी दुश्मन" की कहानी भी गढ़ते हैं, ताकि संकट का खतरा बताकर दमन को सही ठहरा सकें। एर्दोआन ने कथित तख्तापलट करने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मुख्य सचिव व्यक्तिशः पेश हों'

नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के प्रबंधन से संबंधित मामले में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को वर्चुअल रूप से पेश होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और निर्देश दिया कि उन्हें न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से

- सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स के मामले में मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आग्रह को अस्वीकार कर दिया।

पेश होना पड़ेगा।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अपने निर्देशों का बार-बार पालन नहीं करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और मुख्य सचिवों को शारीरिक रूप से उपस्थित होने से छूट देने के सॉलिसिटर जनरल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)